

इन बढ़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य को अपना खर्च बढ़ाना होता है और खर्च की पूर्ति के लिए उसे लोक वित्त में दिये गये तरीकों को अपनाकर विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करना होता है। अतः राज्य के कार्यों व उत्तरदायित्वों का विस्तार होने के साथ ही साथ आजकल लोक वित्त के अध्ययन का महत्त्व एवं क्षेत्र भी निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है।

आधुनिक राज्य के कार्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि जन-कल्याण (welfare) के लिए निम्नलिखित सेवाओं की आवश्यकता होती है—

- (a) आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा (security) तथा सैनिक, पुलिस तथा अन्य सुरक्षात्मक सेवाओं के लिए व्यय की व्यवस्था करना।
- (b) न्याय (justice) अथवा विवादों का निपटारा।
- (c) आर्थिक उद्यमों तथा अन्य ऐसी सेवाओं का नियमन व नियन्त्रण जैसे कि सिक्का ढलाई (coinage), बाट तथा माप (weight and measures), व्यावसायिक गतिविधियों का नियमन (regulation) तथा कुछ उद्यमों (enterprises) की सरकारी स्वामित्व व संचालन।
- (d) शिक्षा, सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, स्वास्थ्य नियन्त्रण तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं के द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कल्याण में वृद्धि करना।
- (e) औपधियों का निर्माण व बिक्री, मद्य की बिक्री, जुआ तथा अन्य समाज विरोधी कार्यवाहियों पर नियन्त्रण लगाकर नैतिक स्तरों का अनियमन करना।
- (f) प्राकृतिक साधनों का संरक्षण।
- (g) परिवहन तथा संचार के साधनों पर नियन्त्रण रखकर तथा ऐसे ही अन्य उपायों द्वारा राज्य की एकता को न केवल बनाये रखना अपितु उसमें और वृद्धि करना।
- (h) सरकार का प्रशासन तथा सरकारी अधिकारियों की सहायता।
- (i) सरकार की वित्तीय व्यवस्था और राजकोषीय नियन्त्रण का प्रशासन।
- (j) समय-समय पर धर्म से सम्बन्धित कार्य।

( 2 ) राजकोषीय क्रियाओं के प्रभाव (Effect of Fiscal Operations)—आर्थिक विश्लेषण (economic analysis) से पता चलता है कि लोक वित्त की कार्यवाहियाँ निवेश (investment) तथा उपभोग पर ठोस प्रभाव

डालती हैं। अतः इनका उपयोग कुल माँग को नियन्त्रित करने तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सरलता से किया जा सकता है। सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने वाली राजकोपीय नीति (fiscal policy) का मुख्य आधार होता है और उसमें परिवर्तन लाकर देश के कुल व्यय को नियन्त्रित किया जा सकता है। किन्तु इस दिशा में सरकारी व्यय केवल तभी सक्रिय होता है तब सरकार किसी निश्चित अवधि में अपनी आय से अधिक या कम खर्च करती है। अतः उन्नत देश अपनी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सदा अच्छी राजकोपीय नीति का ही आश्रय लेते हैं और आर्थिक नियोजन के अन्य सभी उपायों में इसे ही उक्त उद्देश्य की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय मानते हैं।

यद्यपि ऊपर के वक्तव्य की भी कुछ सीमाएँ हैं, फिर भी राष्ट्रीय आय व उत्पादन में स्थायित्व लाने तथा कुछ सीमाओं के अन्तर्गत उसमें वृद्धि करने का यह सर्वाधिक शक्तिशाली तथा एकमात्र अस्त्र रहा है। एक उन्नत अर्थव्यवस्था (advanced economy) में, जहाँ कि प्रति व्यक्ति आय (per capita income) का काफी अच्छा स्तर होता है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि के मार्ग की एक मुख्य बाधा यह होती है कि साधनों में होने वाली वृद्धि की तुलना में माँग नहीं बढ़ती, अतः निवेश के अवसर कम हो जाते हैं। माँग होने का कारण यह होता है कि आय बढ़ने के साथ-साथ सीमान्त उपभोग-प्रवृत्ति (Marginal propensity to consume) घटती जाती है। अतः राष्ट्रीय आय के वितरण में यदि अधिक समानता लाई जाए तो उससे उपभोग कार्य को बल मिलता है और निवेश तथा कुल उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार उच्च आय वाले औद्योगिक देश 'ऊँची मजदूरी व कम लाभ' वाली अर्थव्यवस्था को अपनाकर तथा ऐसी ही अन्य राजकोपीय कार्यवाहियों के द्वारा आय से वितरण में अधिकाधिक समानता लाकर अपनी आय तथा लोगों के जीवन स्तर को काफी ऊँचा उठा सकते हैं। अतः उन्नत देशों में आर्थिक स्थिरता लाने तथा राष्ट्रीय आय व उत्पादन के समान एवं न्यायपूर्ण वितरण के लिए लोक वित्त की कार्यवाहियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है।

अल्पविकसित देशों में भी, सरकार का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास हो तथा राष्ट्रीय उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण (equitable distribution) हो, और राजकोपीय नीति (fiscal policy) इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण अस्त्र बन सकती है।

राजकोपीय नीति देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती है, एक ओर तो यह सरकारी आय (Public income) की मात्रा में वृद्धि करके ऐसा कर सकती है और दूसरी ओर, सरकारी खर्च (public expenditure) की मात्रा तथा उसकी दिशा-परिवर्तन करके। तीन महत्वपूर्ण राजकोपीय उपाय, जिनके द्वारा कि सरकारी खजाने अथवा राजकोष के साधनों में वृद्धि की जा सकती है, ये हैं—कराधान या करारोपण (taxation) जनता के उधार तथा ऋण-प्राप्ति अथवा साख-निर्माण। यह आवश्यक है कि राजकोपीय उपायों का उपभोग इनमें परस्पर पूर्ण तालमेल रखते हुए किया जाए, ताकि लोगों के आर्थिक जीवन पर सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक प्रगति के रूप में इनके सर्वोत्तम तथा व्यापक प्रभाव पड़ें।

यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि इन तीनों उपायों में करधान ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि करों का निर्धारण बुद्धिमत्ता के साथ किया जाए और उनको सावधानी के साथ लागू किया जाए तो करधान राजकोपीय नीति का अत्यन्त प्रभावशाली अस्त्र बन सकता है। विकास के सामान्य कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, करधान का उपभोग निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है—

- (क) उपभोग पर रोक लगाकर या उसमें उसमें कटौती करके उत्पत्ति के साधनों को उपभोग के निवेश की ओर स्थानान्तरित करना।
- (ख) बचत तथा निवेश करने के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन देना।
- (ग) साधनों को जनता के हाथों में से राज्यों के हाथों में देना, जिससे सार्वजनिक निवेश करना सम्भव हो सके।
- (घ) आर्थिक असमानताओं में कमी करना।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये सभी लक्ष्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि तथा उसके वितरण में सुधार के अन्तिम लक्ष्यों से मेल खाते हैं। अतः अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी लोक वित्त की कार्यवाहियों का भारी महत्व है।